आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 13.01.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- चालू वित्त वर्ष में जनवरी के दूसरे सप्ताह में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 दशमलव आठ–दो प्रतिशत बढ़कर 18 लाख 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक हुआ।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा – "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" कार्यक्रम, प्रदेश में सुशासन का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है।
- खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य में मिलावट व नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ज़रिये आमजन का भरोसा मजबूत किया।
- हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर सहित प्रदेश के छह जिलों में कहीं–कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट।

प्रत्यक्ष कर संग्रह

देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 11 जनवरी तक आठ दशमलव आठ–दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18 लाख 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह वृद्धि 8लाख 63 हजार करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट कर प्राप्तियों और व्यक्तिगत करदाताओं के मजबूत योगदान के कारण संभव हुई है। इसी अवधि में टैक्स रिफंड में 17 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे कुल कर संग्रह में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, सकल प्रत्यक्ष कर में चार दशमलव एक–चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इस वित्त वर्ष में अब तक सकारात्मक वृद्धि दर्शाती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12 दशमलव सात प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में प्रतिभूति लेनदेन पर कर से 78 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

जन–जन की सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" कार्यक्रम, प्रदेश में सुशासन का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके लाभ को सीधे जनता तक पहुँचाना है। राज्य सरकार आगे भी इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक नागरिक तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करेगी। "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेशभर में जनसेवा को प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर ठोस प्रगति दर्ज की जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में अब तक 312 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से दो लाख 36 हजार से अधिक नागरिकों का पंजीकरण किया गया है। जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में 25 हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 17 हजार से अधि का निस्तारण किया जा चुका है। सरकारी

सेवाओं को सीधे जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा 35 हजार से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक लाख से अधिक नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है।

जन जन की सरकार

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बुरांसखंडा में "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर" अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने शिविर में 29 विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला कल्याण विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी योजना और किशोरी किट प्रदान की, जबकि उद्यान विभाग के लाभार्थियों को निःशुल्क बीज वितरित किए। कैबिनेट मंत्री ने शिविर में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना, जिसमें 17 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश दिए गए। । उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ मामलों के समाधान में दिक्कतें सामने आईं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 16 जनवरी को सुवाखोली में भी बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक आमजन को इसका लाभ मिल सके।

वहीं, शिविर में कुछ विभागों के सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कैबिनेट मंत्री ने एसडीएम को एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन

प्रदेश में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सुरक्षित भोजन और गुणवत्तापूर्ण दवाओं को लेकर मिलावट और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ज़रिये आमजन का भरोसा मजबूत किया है। वर्ष 2025 में राज्यभर में चलाए गए विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियानों के तहत होटल–ढाबों, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स तक विभागीय टीमें पहुंचीं। इस दौरान 10 हजार 789 उपभोक्ताओं और कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया गया, जबकि 3 हजार 825 खाद्य नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग की टीमों ने जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को संतुलित आहार का संदेश दिया गया।

मौसम

प्रदेश में आगामी 16 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के साथ ही नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी हिस्सों में कहीं–कहीं घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में

कहीं–कहीं पाला पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कहीं–कहीं शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना भी जताई है।

क्रिकेट चयन

राजधानी देहरादून के मियाँवाला क्षेत्र में रहने वाले पार्थ परमार का उत्तराखंड अंडर–14 आयु वर्ग की क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा गत वर्ष दिसंबर माह में छिद्दरवाला में अंडर–14 वर्ग के ट्रायल आयोजित किए गए थे। इन ट्रायल्स में कुल 20 खिलाड़ियों का चयन उत्तराखंड अंडर–14 टीम के लिए किया गया, जिसमें पार्थ परमार का चयन एक बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में हुआ है। अब तक पार्थ लगभग 350 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 24 शतक लगाए हैं और 13 हजार से अधिक रन बनाए हैं। पार्थ ने बताया कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की अंडर–14 टीम आज से 15 दिनों के लिए इंदौर में राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में भाग लेगी। उन्होंने कहा कि वे इस मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर अधिक से अधिक रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में योगदान देना चाहते हैं।

सिटी फॉरेस्ट पार्क

देहरादून स्थित सिटी फॉरेस्ट पार्क की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। पार्क परिसर में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पार्क के संचालन, रख–रखाव और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में पार्क के सभी कर्मचारियों के लिए आई–कार्ड और बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पार्किंग क्षेत्र और पार्क के भीतर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों व माली की तैनाती, रात्रिकालीन सुरक्षा बढ़ाने और पार्क के अंतिम छोर पर सिक्योरिटी हट के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन और अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में पार्क के भीतर किसी भी प्रकार के कंक्रीट या सिविल निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि प्राकृतिक स्वरूप और जैव विविधता सुरक्षित रह सके।